

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 53/2020 (75 एलआरए) अर्जुन सिंह बनाम राजस्थान सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00085)

देशराज पुत्र जमनालाल गुर्जर निवासी मालोनी तहसील खानपुर जिला झालावाड़

..... अपीलांत

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक झालावाड़

..... रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश सहायक वन संरक्षक झालावाड़
दिनांक 27.03.2019 अंतर्गत प्रार्थना पत्र सं. 416/खानपुर/2019

उपस्थित :

- 1 अपीलांत की ओर से अधिवक्ता, श्री देशराज सिंह शक्तावत
- 2 रेस्पोंडेंट की ओर से श्री मुकेश जैन, राजकीय अधिवक्ता



निर्णय

दिनांक 15.10.2020

- 1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सहायक वन संरक्षक के प्रार्थना पत्र सं. 416/खानपुर/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
- 2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक झालावाड़ के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र सं. 416/खानपुर/2019 क्षेत्रीय वन अधिकारी खानपुर की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया परंतु अतिक्रमी उपस्थित नहीं हुआ तथा एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 27.03.2019 को निर्णय पारित किया गया कि देशराज पुत्र जमनालाल गुर्जर निवासी मालोनी द्वारा

15/10/2020
व्यक्ति • कलक्टर एवं
व्यक्ति • विद्या मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज.)

वन खण्ड धानोदा कंला की आराजी ग्राम मालोनी के ख0न0 330 की 2 बीघा भूमि में सरसो बुआई कर वर्ष 2018 में अतिक्रमण किया था जिसके फलस्वरूप इसे धारा 91 एल.आर.एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर मिसल नं. 416/खानपुर निर्णय दिनांक 27.03.2019 से बेदखल किया गया था एवं शास्ती एवं फसल कीमत राशि रु. 2250/- कायम की गई थी पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अप्रार्थीगण को 60 दिवस के सिविल कारावास से सजायाब किया जाता है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

- 3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
- 4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री देशराज सिंह ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं पत्रावली संग्रहसार के सर्वधा विरुद्ध होने से निरस्तनीय है, अपीलार्थी का किसी वन भूमि पर बतौर पश्चातवर्ती अतिचार कर फसल काश्त नहीं की है, अपीलार्थी ने पूर्व में ही उक्त आराजी से कब्जा हटा लिया था और वर्तमान में भूमि रिक्त है, रिपोर्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी दुर्भावना पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की प्रोपर तामील भी नहीं करवाई गई, अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया जिसके कारण अपीलान्ट न्याय पाने से वंचित रहा हैं। अपीलांट भविष्य में भी कब्जा नहीं करेगा इस बात की अण्डरटेकिंग पेश करने को तैयार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2019 का ज्ञान जब हुआ जब उक्त आदेश की पालना में अपीलान्ट को गिरफ्तार करने आये तभी अपीलान्ट द्वारा निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश की है जिसे दिनांक ज्ञान से अवधि मध्य मानी जावे जिसका प्रा0पत्र धारा 5 कानून मियाद मय शपथ पत्र के पृथक से संलग्न किया गया है। उक्त आराजी पर से कब्जा हटाने बाबत क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट भी अपील के साथ संलग्न की गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त तथ्यों के मध्य नजर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.03.2019 अपास्त किया जावे।
- 5 रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट अतिक्रमी है जिसके समर्थन में रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है तथा सहायक वनपाल हाल नाकेदार नाका धानोदा की साक्ष्य ली गई है जो पर्याप्त है। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।



कति 15/11/2020
बिला मजिस्ट्रेट
हालाकर (राज.)

- 6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।
- 7 अपीलान्त के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा-5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर एवं रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता द्वारा प्रा0पत्र का कोई जवाब या खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश नहीं करने के कारण अपीलांत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
- 8 अपीलांत के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अपीलांत को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत को जो प्रथम नोटिस दिया गया उसकी तामील अपीलान्त को पुत्र रोनाक को कराई गई है अपील के साथ संलग्न किये गये आधार कार्ड से स्पष्ट है कि रोनाक नाबालिग है, अन्य दो ओर नोटिस जो पत्रावली में संलग्न है उसमें स्पष्ट नहीं है कि उक्त नोटिस किसी को तामील करवाये गये है एव उनका अपीलान्त से क्या नाता है।
अपीलांत के अधिवक्ता का दूसरा तर्क है कि अपीलान्त पर द्वितीय अतिचार प्रमाणित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि सहायक वनपाल के उक्त बयान किस दिनांक को किसके समक्ष लिये गये अंकित नहीं हैं। बयानों के अंत में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी बयानों का विवरण अंकित नहीं हैं। बयान एवं निर्णय दिनांक 27.03.2019 द्वितीय अतिक्रमण पश्चातवर्ती होना अंकित किया है लेकिन इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व के वर्षों में किये गये निर्णय को एवं उसकी पालना में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को प्रमाणित नहीं किया है।
- 9 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अपीलान्त को विधिवत तामील नहीं होना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर अपीलान्त को सिविल कारावास से दण्डित किया है जो सजा भुगत रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी खानपुर की रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2016, 2017, 2018 में अपीलान्त का अतिक्रमण होना बताया गया है, परन्तु अतिचारी को उक्त आराजी पर से कब बेदखल किया गया पत्रावली से प्रमाणित नहीं होता है। माननीय राजस्व मण्डल ने कई निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि धारा 91 के प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही करके अप्रार्थी की अनुपस्थिति में सुनवाई का अवसर दिये बिना सजा दिया जाना कठोरतम दण्ड है। सजा जैसे कठोरतम दण्ड देने से पूर्व अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। इस प्रकरण में अपीलांत को नोटिस की प्रोपर तामील



व्यक्ति 0 कलकत्ता 20
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

होना भी नहीं पाया जाता है। और न ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने, हटाने का कोई प्रमाण नहीं है, द्वितीय अतिचार किस आधार पर माना गया है स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थी का वर्तमान में उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होना क्षेत्रीय वन अधिकारी खानपुर की रिपोर्ट दिनांक 07.10.2020 से स्पष्ट होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को सिविल कारावास की सजा देने से पूर्व द्वितीय अतिचार प्रमाणित किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शास्ती एवं फसल कीमत राशि 2250/- आरोपित की गई है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि पेनल्टी कितनी लगाई गई है जो लगान की कितनी गुणा है। फसल नीलामी की कार्यवाही भी आदेश होने के उपरान्त ही की जाती है, निर्णय से पहले फसल नीलामी किया जाना एवं नीलामी स्वयं अतिचारी के नाम से होना उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि अतिक्रमी को गिरफ्तार करके कारागृह में भेजा गया है, इसलिए भुगती हुई सजा को छोड़कर शेष सजा निरस्त किये जाने एवं प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। चूंकि अपीलान्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है जो दिनांक 23.09.2020 से सजा भुगत रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास के दण्ड को भुगती सजा तक सीमित रखते हुये शेष सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधि अनुरूप एक माह की अवधि में निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Tensarp
15/10/2020
(दाताराम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति० झालावाड़ स्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

10 निर्णय आज दिनांक 15.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Tensarp
15/10/2020
(दाताराम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति० झालावाड़ स्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)